TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 234
दि. 25.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

उस वक्त रोना मत... सीएम योगी ने दी चेतावनी, माफिया, कब्जा, अपराध पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को सदन के समक्ष रखा, बल्कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का भी तथ्यों के साथ जवाब दिया.

(जीएनएस)।

लखनऊः विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को सदन के समक्ष रखा, बल्कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का भी तथ्यों के साथ जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सुरक्षा, कानून का राज और विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इन्हीं आधारों पर उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया में बदली है. इस दौरान, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि आज जो उपदेश हमारी सरकार को दिए जा रहे हैं, वो उपदेश पहले की सरकारों को दिए होते तो प्रदेश की स्थिति कुछ और होती.

विपक्ष के उठाए सवालों को गंभीरता से लेगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष और सभी दलीय नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में उठाए गए अधिकांश विषय आम जनमानस से जुड़े हुए हैं और प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार गंभीरता से लेती है और उन पर आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी हैं तथा उनकी सहजता और सरलता सदन को सकारात्मक दिशा देती है.

'अगर यह उपदेश उस वक्त दिया होताङ्ग'

उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि विपक्ष में रहते हुए सरकार के कार्यों की आलोचना की जाती है, क्योंकि विरोध में रहने का भी यही औचित्य होता है. आपने सरकार के बजट के आकार और पिछले लगभग साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सरकार के योगदान पर प्रश्न उठाए हैं. इतना अवश्य पूछना चाहूंगा कि यदि आज से लगभग नौझदस वर्ष पहले, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, आज जो आपने उपदेश यहां दिए हैं, वे उस समय की सरकार को दिए होते तो संभवतः प्रदेश की स्थिति कुछ और होती.

2017 से पहले और बाद का अंतर प्रदेश की जनता देख रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता, अव्यवस्था और पहचान के संकट की जो स्थिति बनी थी, उसके लिए कौन उत्तरदायी था यह उत्तर प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है. आपने यह स्वीकार किया है कि अपराधियों और माफियाओं के प्रति सरकार की नीति स्पष्ट और कठोर होनी चाहिए और यह हमारी सरकार ने करके भी दिखाया है. राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति और उसे लागू करने की इच्छाशक्ति आवश्यक होती है. इसके चार प्रमुख आयाम हैं और उन चारों पर सरकार ने प्रभावी ढंग से कार्य किया है.

2017 के बाद यूपी की छवि में आया बदलाव

कोई भी व्यक्ति, समाज या संस्था, सबसे पहले सुरक्षा चाहता है. कानून का राज हो, हर व्यक्ति, हर बेटी, हर व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे यह किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में जो बदलाव आया है, वह देश और दुनिया दोनों के सामने है. पहले प्रदेश की छवि अच्छी नहीं थी, यह हम सभी को पीड़ा देता था। आज प्रदेश के भीतर या बाहर जाने पर लोग स्वयं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है, दंगे नहीं हैं, अराजकता नहीं है.

बेटी किसी भी पक्ष की हो उसे न्याय मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय कैसे होता है, इसका उदाहरण भी हमारे सामने है. पूजा पाल प्रकरण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है. आपके समय में माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी, लेकिन आज सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि बेटी किसी भी पक्ष की हो, उसे न्याय हर हाल में मिलेगा. यह केवल सत्ता या विपक्ष का विषय नहीं, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा और सम्मान का विषय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस रिद्धिमा यादव की बात यहां कही जा रही है उसे भी न्याय हमारी सरकार जरूर देगी. मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जों के सवाल पर कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, किसी भी स्मारक, पौराणिक स्थल या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा. अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। सरकारी भूमि गरीबों के लिए है, न कि माफिया के लिए.

गरीब और वंचितों के लिए लाए गए बिल पर सपा का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि इस सदन में जब ग्रामीण अभिलेख विधेयक लाया गया तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया. ग्रामीण अभिलेख से संबंधित संशोधन विधेयक पहली बार गरीब को उसके मकान का वैधानिक अधिकार देता है. यह अधिकार महिला सदस्य के नाम पर दर्ज होगा, जिससे वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेगी. लेकिन यदि कोई माफिया या असामाजिक तत्व सरकारी भूमि पर कब्जा कर अनैतिक गतिविधियाँ करेगा, तो उस पर कठोरतम कार्यवाही होगी. उन्होंने कहा कि यही सुरक्षा का वातावरण है, जिसने उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और जिसके कारण आज प्रदेश में निवेश आ रहा है. यह परिवर्तन परिणाम आधारित है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका उत्तर दिया है और आगे भी देती रहेगी.

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम में आने वाली नागरिकों की प्रस्तुतियों का सामूहिक प्रयासों से आवश्यक निवारण लाने हेतु राज्य सरकार के विभागों से अनुरोध

किसानों के प्रति मुख्यमंत्री की विशेष संवेदनशीलता

- जूनागढ और मेहसाणा जिलों के किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तत्काल भुगतान करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश
- कालोलनगरपालिका के सड़क-मार्ग एवं नाली के कार्यों की क्वालिटी में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के दिशानिर्देश
- मुख्यमंत्री के समक्ष दिसंबर 2025 के राज्य 'स्वागत' में 97 से अधिक प्रस्तुतिकताओं की प्रस्तुतियां आईं

गांधीनगर, 24 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को दिसंबर 2025 के राज्य 'स्वागत' में प्रस्तुति करने आए नागरिकों की प्रस्तुतियां प्रत्यक्ष रूप से सुनकर उनके उचित निवारण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए।

इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के विभागों एवं प्रशासन के अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया कि 'स्वागत' में आने वाली प्रस्तुतियों का निवारण सामूहिक प्रयासों से किया जाना चाहिए।

हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होने वाले 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के उपक्रम में दिसंबर 2025 का राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम बुधवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान राज्य भर से 97 से अधिक प्रस्तुतिकर्ता अपनी प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हुए। इतना हीं नहीं, जिला स्वागत की 1,284 तथा तहसील स्वागत की 2,458 प्रस्तुतियों-प्रश्नों के संदर्भ में जिला तहसील स्तर पर निवारण की कार्यवाही भी की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उनके समक्ष आई प्रस्तुतियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके उचित निवारण के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने जूनागढ जिले की केशोद तहसील के एक धरती पुत्र को उसके खेत तक जाने के लिए रास्ता स्थानीय स्थिति की आवश्यक जांच कर उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए।

इसके अतिरिक्त, श्री पटेल ने कलेक्टर को सीपू योजना के अंतर्गत साबरमती सरस्वती लिंक कैनाल योजना में मेहसाणा के किसान की अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नगरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तथा नागरिक सुविधाओं के कार्यों में क्वालिटी बनी रहे, यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया तथा ऐसे कार्यों में लापरवाही या निष्क्रियता बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वापी नगर पालिका क्षेत्र में संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि में अंडरग्राउंड ड्रेनेज कनेक्शन हेतु हो रहे अवरोधों को दूर कर यह कनेक्शन तत्काल देने तथा बाबरा तहसील के प्रस्तुतिकर्ता को सरकार द्वारा आवंटित निःशुल्क आवासीय प्लॉट को गांव के नमूने में दर्ज कर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर, प्रधानमंत्री 25 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों के मान-सम्मान के लिए लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है जो भारत की राष्ट्रीय यात्रा और नेतृत्व की विरासत दर्शाती है

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसम्बर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाएंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे, प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों की विरासत का मान-सम्मान करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से प्रेरित होकर, राष्ट्र प्रेरणा

स्थल भारत के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि देगा, जिनके नेतृत्व ने देश की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकासात्मक यात्रा पर गहरा प्रभाव डाला।

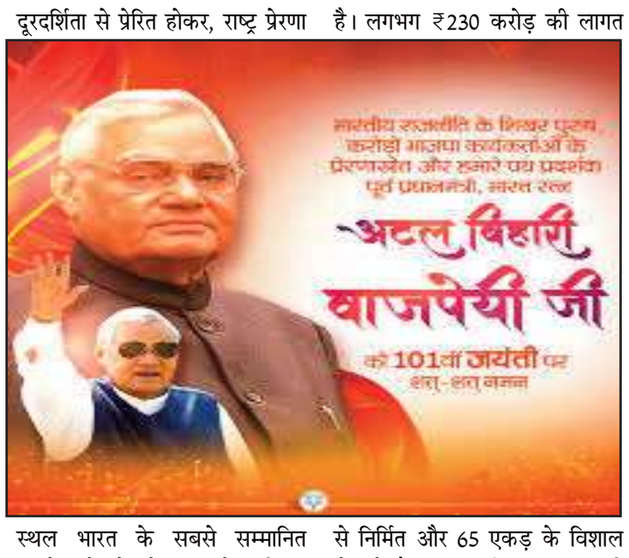

राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। लगभग ₹230 करोड़ की लागत से निर्मित और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह परिसर एक स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में परिकल्पित है, जो नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

इस परिसर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक हैं। इसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है जिसे कमल के फूल के आकार में बनाया गया है, जो लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह संग्रहालय भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है।

जो आगंतुकों को एक आकर्षक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और उम्मीद है कि यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

उत्तराखण्ड:विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों को लेकर 167 नए अफसरों की तैनाती

उत्तराखण्ड में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों को लेकर 167 नए अफसरों की तैनाती की गई है। प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के मध्यनजर 167 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में 70 विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम स्तर के 70 ईआरओ और तहसीलदार स्तर के 268 एईआरओ तैनात हैं।

एलवीएम3 ने सबसे भारी पेलोड की सफलता के साथ विश्व स्तरीय विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया-डॉ. जितेंद्र सिंह

यह मिशन भारत की भारी-भरकम मालवाहक और वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

(जीएनएस)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह को ले जाने वाले एलवीएम3-एम6 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर इसरो टीम को बधाई दी। केन्द्रीय मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती ताकत, विश्वसनीयता और वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत करते हुए लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, भारत में एलवीएम3-एम6 मिशन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस मिशन में भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा अब तक के सबसे भारी उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है। यह मिशन अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में देश की स्थिति को और मजबूत करता है और भारी-भारित प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने की उल्लेखनीय सफलता दशार्ता है।

अंतरिक्ष विभाग के सचिव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसए) के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने घोषणा की कि एलवीएम3-एम6 प्रक्षेपण यान ने सफल प्रदर्शन करते हुए ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह को उसकी निर्धारित निम्न पृथ्वी कक्षा में सटीक रूप से स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह स्वदेशी प्रक्षेपण यान का उपयोग करके भारतीय धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है और एलवीएम3 का तीसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मिशन प्रक्षेपण यान की उत्कृष्ट विश्वसनीयता और विश्वस्तरीय प्रदर्शन को दशार्ता है, इससे यह वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो गया है।

इस मिशन में उपयोग किया गया उपग्रह, ब्लू बर्ड ब्लॉक-2, अगली पीढ़ी के उपग्रह समूह का हिस्सा है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 26 दिसंबर को गुजरात के वटवा में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के 'भविष्य निधि भवन' का उद्घाटन करेंगे

(जीएनएस)।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 26 दिसंबर, 2025 को गुजरात के वटवा स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय के नवनिर्मित 'भविष्य निधि भवन' का उद्घाटन जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में करेंगे।

वर्तमान में ईपीएफओ का वटवा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात के छह जिलों - अहमदाबाद (आंशिक), आनंद, खेड़ा, अमरेली, बोटाद और भावनगर - में कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को सेवाएं प्रदान करता है। दिसंबर 2025 तक इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में 7,013 अंशदायी प्रतिष्ठान, 3,97,676 अंशदायी सदस्य और लगभग 21,000 पेंशनभोगी शामिल हैं।

नवनिर्मित भविष्य निधि भवन लगभग 10.12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है , जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 1,723.46 वर्ग मीटर है। इस भवन में ग्राहकों, पेंशनभोगियों, दिव्यांगजनों और संगठन के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संचयन प्रणाली, केंद्रीकृत वातानुकूलन, पावर बैक-अप जनरेटर और भूमिगत पार्किंग जैसी आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (एनएच-48), रबारी कॉलोनी मेट्रो स्टेशन और बीआरटीएस सीटीएम बस स्टॉप के निकट रणनीतिक रूप से स्थित इस नई सुविधा से सभी हितधारकों के लिए बेहतर पहुंच, निर्बाध कनेक्टिविटी, अधिक कुशल, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण वातावरण मुहैया होने की उम्मीद है।

बांग्लादेश की महिला पत्रकार नाजनीन मुन्नी को क्यों मारना चाहते हैं यूनुस के गुंडे? सामने आई चौंकाने वाली वजह

बांग्लादेश में मीडिया की आजादी पर खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले नामचीन अखबारों के दफ्तरों में आग लगाई गई और अब महिला एंकर यूनुस के गुर्गों के निशाने पर हैं। ग्लोबल टीवी बांग्लादेश की एक जानी-मानी न्यूज एंकर नाजनीन मुन्नी को हटाने की मांग को लेकर चैनल को गंभीर धमकी दी गई है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जिससे मीडिया संस्थानों में डर का माहौल है। चैनल में घुसकर दी धमकी, ढाका में स्थित ग्लोबल टीवी के मुख्यालय पर इस हफ्ते कुछ युवाओं का एक समूह पहुंचा। उन्होंने चैनल प्रबंधन को साफ चेतावनी दी कि अगर नाजनीन मुन्नी को उनके पद से नहीं हटाया गया, तो टीवी चैनल के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाएगा।

सम्पादकीय

यूएस : यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में दबे हैं कई राज

अमेरिकी न्याय विभाग ने कुख्यात फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े मामलों की जांच से संबंधित 13 हजार से ज्यादा फाइल सार्वजनिक कर दिए हैं। वे दस्तावेज उस कानून के तहत जारी किए गए हैं। जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे।

हालांकि लंबे इंतजार के बावजूद इन फाइलों से अभी तक कोई चौंकाने वाले खुलासे नहीं हुए हैं। ज्यादातर दस्तावेजों को भारी रूप से ब्लैक किए गए हैं। जेफरी एपस्टीन की मौत हो चुकी है। अमेरिकी संसद ने एक कानून पास किया था, जिसके तहत शुक्रवार तक सभी फाइलों को पूरी तरह सार्वजनिक करना जरूरी था। लेकिन अब तक कुछ ही दस्तावेज जारी किए गए हैं, वो भी कई जगह भारी काट-छांट के साथ। इन दस्तावेजों को सार्वजनिक कराने के लिए दबाव बनाने वाले सांसदों ने विभाग की कोशिश को गैर-गंभीर बताया है। वहीं कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी ज्यादा काट-छांट से साजिश से जुड़ी धाराएं और मजबूत हो सकती हैं। जारी सामग्री में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोटो भी जारी किया गया है, हालांकि उन्हें बचाने की भी पूरी कोशिश की गई है। फाइलों में एक फोटो शामिल है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एपस्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिलेन मैक्सवैल (एपस्टीन की गर्लफ्रेंड) साथ नजर आ रहे हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन फाइलों के हटने को लेकर अब तक कोई सफाई नहीं दी है। जो फाइले सार्वजनिक की गईं हैं उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़े एंड्रयू माउंटबेटनविंड सर, मशहूर गायक मिक जैगर और माइकल जैक्सन के नाम शामिल हैं। हालांकि इन फाइलों में किसी का नाम होना या उनकी तस्वीर होना यह साबित नहीं करता कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। जिन लोगों के नाम इन दस्तावेजों में आए हैं या पहले भी एपस्टीन से जुड़े मामलों में सामने आए थे, उनमें से कई ने किसी भी तरह की गलत गतिविधि से इंकार किया है। जारी की गईं कई तस्वीरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन स्विमिंग पूल में दो महिलाओं के साथ तैरते दिखते हैं। यह तस्वीर हॉट टब की लगती है। 1990 के दशक और 2000 के शुरूआती सालों में बिल क्लिंटन की जेफरी एपस्टीन के साथ कई बार तस्वीरें ली गईं थीं। क्लिंटन हालांकि यह कहते हैं कि उन्हें एपस्टीन के यौन अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। दस्तावेजों के मुताबिक जेफरी एपस्टीन ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात एक 14 साल की लड़की से कराई गई थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने जो फाइलें जारी की हैं उनमें राष्ट्रपति ट्रंप का भी जिक्र है। अदालत के कागजों के मुताबिक यह मुलाकात फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में 1990 के दशक की बताई जाती है। दस्तावेज में कहा गया है कि एपस्टीन ने ट्रंप को कोहनी मारकर लड़की की ओर इशारा किया और मजाकिया अंदाज में पूछा कि यह अच्छी है ना..? ट्रंप मुस्कराए और सहमति से सिर हिलाया। दस्तावेज के मुताबिक इसे लेकर दोनों हंसे थे और लड़की को असहज महसूस हुआ। लेकिन उस समय वह इतनी छोटी थी कि उस हंसी की वजह वे समझ नहीं पाईं। सर्वाइवर का आरोप है कि एपस्टीन ने कई सालों तक उसे बहकाया और उसका शोषण किया। हालांकि अदालत में दायर कागजों में लड़की ने ट्रंप पर कोई आरोप नहीं लगाया है। इन दस्तावेजों पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस की प्रावक्ता एबिगेल जैक्सन ने बयान दिया कि ट्रंप प्राशासन इतिहास का सबसे पारदशा प्राशासन है। उन्होंने कहा कि हजारों पन्नों के दस्तावेज जारी किए गए हैं और हाउस ओवरसाइट कमेटी की जांच में सहयोग किया गया है। उधर डिप्टी अटाना जनरल टॉड ब्लांश ने कहा है कि कई लाख पन्नों की अभी भी जांच चल रही है। ये दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने इससे जुड़ी तस्वीर के गायब होने पर सवाल उठाए हैं और पूछा कि और क्या छिपाया जा रहा है? अभी तो खेला शुरू हुआ है, आगे-आगे देखें होता है क्या?

विशाखापत्तनम में पेसा महोत्सव 2025 का भव्य समापन

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल ने विशाखापत्तनम में दो दिवसीय पेसा महोत्सव के प्रतिभागियों को पेसा दिवस के अवसर पर संबोधित किया; उन्होंने जनजातीय अधिकारों के लिए संवैधानिक समर्थन पर बल दिया एवं जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया

पेसा दिवस के अवसर पर पेसा पोर्टल का शुभारंभ, पेसा संकेतक, जनजातीय भाषाओं में पेसा प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले पर ई-पुस्तक का अनावरण किया गया

(जीएनएस)।

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल ने विशाखापत्तनम में 23-24 दिसंबर 2025 को आयोजित दो दिवसीय पेसा महोत्सव के प्रतिभागियों को पेसा दिवस (24 दिसंबर 2025) के अवसर पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) जल, वन, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय अधिकारों को मजबूत संवैधानिक समर्थन प्रदान करता है और उन्होंने जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया।

इस महोत्सव में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना सहित सभी दस पेसा राज्यों के जनजातीय समुदायों के पंचायत प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों, कारीगरों, शिल्पकारों एवं सांस्कृतिक कलाकारों की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई। प्रतिभागियों ने कबड्डी, तीरंदाजी, पेसा दौड़ और जनजातीय प्रदर्शन खेलों जैसे आयोजनों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही जनजातीय भोजन, शिल्प, कला, संस्कृति, नृत्य एवं परंपराओं की प्रदर्शनियों ने जनजातीय विरासत को एक जीवंत राष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

प्रोफेसर बघेल ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, साथ ही राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए दस्तावेजीकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं एवं परंपराओं के अनुरूप ग्राम स्तर पर तैयार की गई सहभागी विकास योजनाएं जनजातीय समाज की प्रगति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि पेसा महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय युवाओं को संबद्ध करना, नेतृत्व कौशल बढ़ाना, जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना और "मेरी परंपरा, मेरी पहचान" की भावना को मजबूत करना है।

श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अनुसूचित क्षेत्रों में जल, वन एवं भूमि की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना के रूप में पेसा अधिनियम के महत्व पर बल दिया, साथ ही जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाता है, समुदाय-आधारित निर्णय को सक्षम बनाता है और ग्राम सभा को लोकतांत्रिक भागीदारी के केंद्र में रखता है। उन्होंने कहा कि पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं द्वारा लिए गए निर्णय भारत की लोकतांत्रिक संरचना की वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये जनजातीय समुदायों को अपने संसाधनों का प्रबंधन एवं अपने विकास की दिशा तय करने में सक्षम बनाते हैं।

श्री भारद्वाज ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने पेसा नियमों के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है, जिससे झारखंड पेसा नियमों की अधिसूचना के साथ आगे बढ़ने वाला 10 पेसा राज्यों में से नौवां राज्य बन गया है।

श्री शशि भूषण कुमार, प्रधान सचिव, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और पेसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पेसा जिलों एवं अनुसूचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रीत करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

महोत्सव के दूसरे दिन यानी पेसा दिवस के दिन, कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया गया, जिनमें पेसा पोर्टल, पेसा संकेतक, जनजातीय भाषाओं में पेसा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले पर ई-पुस्तक शामिल हैं। श्री विवेक भारद्वाज और श्री शशि भूषण कुमार ने पंचायती राज मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से इनका अनावरण किया। ये पहलें राज्यों में प्रभावी पेसा कार्यान्वयन के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, निगरानी एवं क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की विविध जनजातीय एवं लोक विरासत का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य और राज्यवार प्रस्तुतियां जैसे गुस्साड़ी (तेलंगाना), गवारी (राजस्थान), धेमसा (ओडिशा) तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य शामिल थे। इस कार्यक्रम में चुनिंदा जनजातीय खेलों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रतिभागी टीमों को सम्मानित किया गया।

समापन सत्र में पेसा दौड़, कबड्डी एवं तीरंदाजी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, साथ ही जनजातीय प्रदर्शन खेलों के प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में, पेसा महोत्सव की मशाल छत्तीसगढ़ को सौंपी गई, जिससे यह पेसा महोत्सव का अगला मेजबान राज्य के रूप में चिन्हित हुआ।

पेसा दौड़ (पुरुष वर्ग) में श्री अतुल चिधाडे (महाराष्ट्र) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनके बाद श्री सूरज मशी और श्री मनोज हिलिन (दोनों महाराष्ट्र से) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में सुश्री राज कुमारी (राजस्थान) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनके बाद सुश्री हीरा सांगा (झारखंड) और सुश्री प्रिया (हिमाचल प्रदेश) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।

महिला तीरंदाजी में, सुश्री खुशी नानोमा (राजस्थान) ने स्वर्ण पदक, सुश्री अनुराधा कुमारी (झारखंड) ने रजत पदक और सुश्री अंबिका (ओडिशा) ने कांस्य पदक जीता।

पुरुष तीरंदाजी में श्री कृष्ण पिंगुआ (झारखंड) ने स्वर्ण, श्री बद्रीलाल मीना (राजस्थान) ने रजत और श्री दिनेश मुर्मू (झारखंड) ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी इंडोर स्टेडियम में 23 दिसंबर 2025 को आयोजित कबड्डी प्रतियोगिताओं में, मध्य प्रदेश ने पुरुष वर्ग में जबकि झारखंड ने महिला वर्ग में जीत दर्ज की।

पेसा अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, सभी 10 पेसा राज्यों में ग्राम सभाओं के माध्यम से जनभागीदारी में पेसा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो संदेशों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दीं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों ने भी पेसा महोत्सव की सराहना की और इसे जनभागीदारी को बढ़ावा देने, जमीनी स्तर पर स्वशासन को सुदृढ़ करने एवं लोक संस्कृति में निहित लोक उत्सव वाला पहल कहा।

विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी स्टेडियम में 23-24 दिसंबर 2025 को आयोजित दो दिवसीय पेसा महोत्सव का समापन आज पेसा दिवस के साथ हुआ, जिसमें पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर स्वशासन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

गांवों से नए परिदृश्य की ओर : सुशासन कैसे बदल रहा है ग्रामीण भारत की कहानी

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के गुना जिले के श्रीपुरा गांव में एक शांत सुबह में श्रीमती सरिता सैनी अपने दिन की शुरूआत न केवल स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए बल्कि सुखाने और भंडारण के लिए सब्जियों को छांटने से करती हैं, जिससे उनकी उपज को उस अवधि के दौरान भी बेचा जा सकता है जब खेती की गतिविधियां सीमित होती हैं। एकता स्व-सहायता समूह के सदस्य के रूप में उन्हें शुरूआत में सीमित संसाधनों, अपर्याप्त तकनीकी ज्ञान और आय असुरक्षा से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम में उनका शामिल होना एक महत्वपूर्ण बदलाव था। संस्थागत समर्थन, क्षमता निर्माण और पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से उन्हें एक लाख रुपए मूल्य का सोलर ड्रायर प्राप्त हुआ। वर्तमान में वह सब्जी की खेती को सौर ऊर्जा से सूखने के साथ एकीकृत करती है, जिससे साल भर बाजार पहुंच सुनिश्चित होती है और लगभग 20,000 रुपये की स्थिर मासिक आय होती है। उनकी यह यात्रा दशार्ती है कि कैसे अच्छी तरह से डिजाइन किए गए शासनीय ढांचे स्थानीय उद्यमिता को उत्प्रेरित कर सकते हैं जब अवसरों को लक्षित समर्थन द्वारा पूरा किया जाता है ।

सरिता जैसे ग्रामीण, शासन के व्यापक ढांचे में निहित हैं जो लोगों को विकास प्रक्रियाओं के मूल में रखता है। विकेंद्रीकरण लंबे समय से भारत के ग्रामीण परिवर्तन का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्थानीय संस्थानों के पास स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान है। ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और समुदाय-आधारित संस्थानों को मजबूत करके, शासन को नागरिकों के करीब लाया जाता है, जिससे भागीदारी योजना और अधिक उत्तरदायी परिणाम सक्षम होते हैं। यह प्रतिमान विकास को योजनाओं की शीर्ष-डाउन डिलीवरी से एक सहयोगी मॉडल में स्थानांतरित करता है जिसमें समुदाय सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करते हैं, प्राथमिकता-निर्धारण और जमीनी स्तर पर परिणामों की निगरानी में योगदान करते हैं।

इस ग्रामीण विकास पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम हैं, प्रत्येक को पारस्परिक रूप से सुदृढ़ तरीके से कार्य करते हुए ग्रामीण आजीविका के विशिष्ट आयामों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) दुनिया की सबसे बड़ी आजीविका पहलों में से एक के रूप में उभरी है , जिसने 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया है और संस्थागत वित्त तक पहुंच के साथ-साथ निरंतर सहायता प्रदान की है। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत लखपति दीदी पहल उन

एसएचजी सदस्यों को मान्यता देती है जिनके परिवारों की वार्षिक आय विविध आजीविका गतिविधियों के माध्यम से कम से कम एक लाख रुपये है जो निर्वाह-आधारित आजीविका से अधिक आर्थिक स्थिरता की ओर बदलाव को दशार्ता है। 24 दिसंबर, 2025 तक, 10.29 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को डी ए वाई झ एन आर एल एम के अंतर्गत एस एच जी में जुटाया गया है।

रोजगार सुरक्षा ग्रामीण लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 , को अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाने के साथ-साथ आय की सहायता भी मिलती है। वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से, कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को 48% से बढ़ाकर 56.74% करना, आधार-आधारित सक्रिय श्रमिकों को 76 लाख से बढ़ाकर 12.11 करोड़ करना, और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक वेतन भुगतान को 37% से बढ़ाकर 99.99% करना शामिल है, जो बढ़ी हुई पारदर्शिता और वित्तीय को दशार्ता है। समावेशन उभरती ग्रामीण आर्थिक स्थितियों के जवाब में, सरकार ने रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के लिए विकसित भारत-गारंटी पेश की है, जो 125 दिनों के वेतन रोजगार की बढ़ी हुई वैधानिक गारंटी का प्रस्ताव करती है और एक अभिसरण-संचालित, संतृप्ति-उन्मुख योजना ढांचे के भीतर ग्रामीण कार्यों को संचालित करती है, जो विकसित भारत@2047.की दृष्टि से संरेखित है।

सुरक्षित आवास और विश्वसनीय कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता के प्रमुख निर्धारक हैं। 24 दिसंबर, 2025 तक, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, 3.86 करोड़ स्वीकृत घरों में से 2.92 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7.87 लाख किलोमीटर तक फैली 1.84 लाख सड़कों का निर्माण किया गया है। इस तरह के बुनियादी ढांचे के निवेश भौतिक अलगाव को कम करते हैं और गतिशीलता और सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर कनेक्टिविटी को आर्थिक अवसर में बदलते हैं। इसका एक उदाहरण झारखंड के गोड्डा जिले में मिलता है, जहां पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 285.45 लाख रुपये की लागत से 5.68 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़क का निर्माण किया गया है। इससे वंचित गांवों के लिए कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सड़कें बस्तियों को प्रमुख बाजार गलियारों और आसपास के पीएमजीएसवाई नेटवर्क से जोड़ती हैं, जिससे 10,000 से अधिक निवासियों को सीधे लाभ मिलता है। बाजारों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाकर, हस्तक्षेप ने आजीविका के अवसरों को मजबूत किया है, जो स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में सुनियोजित ग्रामीण बुनियादी ढांचे की भूमिका को प्रदर्शित करता है।

कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यापक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने 1 सितंबर 2025 तक 17.71 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 11.51 लाख उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान की है, जिससे ग्रामीण युवाओं को श्रम बाजार की मांग के अनुरूप कौशल से तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को महत्वपूर्ण आय सहायता प्रदान करता है, जो भेद्यता की अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है। समानांतर पहलों में, जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, क्रमशः एक आदर्श गांव और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जो दशार्ता है कि कैसे लक्षित हस्तक्षेप और ग्रामीण-शहरी अभिसरण चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में सेवा वितरण और जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं।

डिजिटलीकरण इस परिवर्तन के एक शक्तिशाली प्रवर्तक के रूप में उभरा है। इंडियामार्ट पर अपने केले के फाइबर उत्पादों को सूचीबद्ध करके और ऑनलाइन खरीदारों के साथ जुड़कर, उत्तर प्रदेश के समैसा गांव में मां सरस्वती ग्राम संगठन ने सूरत, अहमदाबाद और कानपुर जैसे औद्योगिक केंद्रों से थोक ऑर्डर हासिल करते हुए, स्थानीय सीमाओं से परे अपनी बाजार पहुंच का विस्तार किया। बढ़ी हुई डिजिटल दृश्यता और ऑनलाइन बाजार लिंकेज ने एसएचजी को बेहतर कीमतों (150 रुपये से 200 रुपये प्रति किलोग्राम) पर नियंत्रण रखने और परिचालन को बढ़ाने में सक्षम बनाया, जिससे ग्रामीण उत्पादकों को व्यापक बाजारों के साथ एकीकृत करने में डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका प्रदर्शित हुई। संस्थागत स्तर पर, देश भर में ग्राम पंचायतें पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए ईग्रामस्वराज और सभासार जैसे डिजिटल शासन प्लेटफार्मों को तेजी से अपना रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 तक, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास योजनाएं ऑनलाइन अपलोड कर दी थीं, और 2.4 लाख से अधिक ने वित्त आयोग अनुदान से संबंधित डिजिटल लेनदेन पूरा कर लिया था, जो जवाबदेह स्थानीय शासन की ओर बदलाव को दशार्ता है। इन प्रयासों को पूरा करते हुए, भारतनेट कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 24 दिसंबर, 2025 तक 2.14 लाख से अधिक पंचायतें भारतनेट से जुड़ चुकी हैं।

इन विविध पहलों को रेखांकित करने वाला एकीकृत सिद्धांत अभिसरण है, जिसमें संसाधनों, योजना प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तंत्रों को संरेखित करना शामिल है। मिशन अंत्योदय डेटा-संचालित निदान के माध्यम से इस दृष्टिकोण का प्रतीक है जो विकासात्मक अंतराल की पहचान करता है और लक्षित, बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों को सूचित करता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों, अपशिष्ट से धन पहल, वित्तीय समावेशन और कौशल-आधारित आजीविका सहित विभिन्न डोमेन में प्रयासों को एकीकृत करके, अभिसरण खंडित प्रयासों को विकास के सुसंगत मार्गों में बदल देता है । इस ढांचे को लागू करते हुए, सहभागी योजना पहल जैसे पीपुल्स प्लान अभियान और विकासशील पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण समुदाय के नेतृत्व वाले निर्णय लेने को संस्थागत बनाते हैं। ग्राम सभाओं को योजना के केंद्र में रखकर, ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय प्राथमिकताएँ सामूहिक सहमति के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं और समन्वित और अभिसरण कार्रवाई के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

जैसा कि भारत सुशासन दिवस मनाता है तो ग्रामीण विकास का अनुभव बताता है कि शासन अपना सबसे बड़ा प्रभाव तब प्राप्त करता है जब यह समावेशी, उत्तरदायी और भविष्य की ओर उन्मुख होता है। वर्तमान प्रयास में अभिसरण को मजबूत करने, विकेंद्रीकरण को गहरा करने और लचीली ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने पर जोर देते हैं। बढ़ी हुई रोजगार गारंटी, एकीकृत योजना ढांचे और पारदर्शिता और जवाबदेही पर निरंतर ध्यान के साथ, ग्रामीण विकास को अलग-अलग योजनाओं के एक सेट के रूप में नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर निरंतर ध्यान देने के रूप में पुनः संकल्पित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास को योजनाओं के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि साझा समृद्धि के सुसंगत मिशन के रूप में पुनर्कल्पित किया जा रहा है। श्रीपुरा में सरिता सैनी के सोलर ड्रायर की कहानी, हालांकि पैमाने में मामूली है, इस यात्रा के सार को दशार्ती है, यह दशार्ती है कि कैसे अच्छी तरह से डिजाइन की गई नीतियां, जब ईमानदारी और उद्देश्य के साथ लागू की जाती हैं, तो रोजमर्रा की आजीविका में ठोस सुधार लाती हैं।

अरावली के लिए क्यों जान देने को तैयार है राजस्थान?
जानें इतिहास से आस्था तक के अनकहे राज

(जीएनएस)।

अरावली पर्वत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। खास तौर पर राजस्थान में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। राजस्थान के लिए यह सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि राजस्थान की जीवनरेखा है। यहां के लोग इसे एक संरक्षक और देवता के रूप में देखते हैं। हजारों साल पुरानी यह पर्वतमाला मरू प्रदेश की जलवायु, संस्कृति, आस्था और अस्तित्व से जुड़ी है।

यही वजह है कि अरावली को बचाने के लिए लोग जान की बाजी तक लगाने को तैयार रहते हैं। इस पहाड़ ने इतिहास में खिलजी से लेकर मुगलों के आक्रमण से बचाने का काम किया है। अरावली की तलहटी में बने लोहागढ़ किले को अंग्रेज 11 बार जीतने की कोशिश कर भी सफल नहीं हो पाए थे। जानें राजस्थान के लिए अरावली क्यों महत्वपूर्ण है।

मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक रोकने में कामयाब

राजस्थान के ज्यादातर विशाल किले अरावली की तराई में हैं। मुगल बादशाह अपने लंबे शासनकाल में इनमें से कई किलों को जीत नहीं पाए थे। इसमें कुंभलगढ़, लोहागढ़ जैसे किले शामिल हैं। पहाड़ों की तराई में होने की वजह से आक्रमणकारियों के लिए इसे पार करना कठिन होता था। राजस्थान में गर्मी और सर्दी दोनों बहुत ज्यादा पड़ती है और इस वजह से भी आक्रमणकारियों को पीछे हटना पड़ता था। यही वजह है कि अंग्रेजों को भी यहां मुंह की खानी पड़ती थी।

मरुस्थल को रोकने वाली दीवार

अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान के बीच एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। यह रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों और मरुस्थलीकरण को आगे बढ़ने से रोकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अरावली न होती, तो आज राजस्थान का बड़ा हिस्सा पूरी तरह रेगिस्तान में तब्दील हो चुका होता। राजस्थानी लोकगीतों में अरावली को एक विजयी देवता की तरह माना जाता है जो धूल की आंधियों और प्रदेश को रेगिस्तान में बदलने से रोकने में प्राकृतिक रक्षक बनता है।

जल का स्रोत और जीवनदायिनी

पानी की कमी वाले राजस्थान में अरावली को 'जलदाता' कहा जाता है। बनास, बेड़च, लूनी, साबरमती और कोठारी जैसी कई प्रमुख नदियों का उद्गम इसी पर्वतमाला से होता है। प्राचीन काल से यहां के लोग जल संरक्षण के लिए पहाड़ियों, झीलों और कुंडों पर निर्भर रहे हैं। अरावली भूजल स्तर को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है।

धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था का केंद्र

अरावली क्षेत्र में अनेक पवित्र धार्मिक स्थल स्थित हैं। माउंट आबू का गुरु शिखर भगवान दत्तात्रेय से जुड़ा माना जाता है। देलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़, और पुष्कर जैसे तीर्थस्थल इसी श्रृंखला में बसे हैं। लोक देवता पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी का संबंध भी अरावली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इन मान्यताओं के कारण अरावली केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक धरोहर भी है। राजस्थान के भील और मीणा जैसे आदिवासी समुदाय अरावली को एक मां की तरह पूजते हैं। कई जनजातीय समुदायों में अरावली को पिता जैसा देव माना गया है।

खनिजों का भंडार

- अरावली तांबा, जस्ता और सीसा जैसे खनिजों से समृद्ध रही है, जिसने सदियों तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया।

- इसके जंगल वन्यजीवों, औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों का घर हैं। भील और गरासिया जैसी जनजातियां आज भी अपने जीवनयापन के लिए अरावली पर निर्भर हैं।

- अरावली राजस्थान की जलवायु को संतुलित रखती है, बारिश लाने में मदद करती है और उपजाऊ भूमि की रक्षा करती है।

- यही कारण है कि राजस्थान के लोग अरावली को केवल पहाड़ नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का रक्षक मानते हैं। कहा जाता है कि अरावली बची है, तो राजस्थान बचा है।

हालिया फैसले पर क्या है विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निर्देश दिया है कि 100 मीटर से कम ऊंची वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रृंखला में नहीं माना जाएगा। स्थानीय लोग इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इससे खनन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता और यह जलवायु के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस पर्वतमाला को बिल्डर्स को सौंपना चाहता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो की फेज V (A) परियोजना के हिस्से के रूप में तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज-श (ए) परियोजना के हिस्से के रूप में तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी दी है: 1. आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी), 2. एरोसिटी से आई.जी.डी. एयरपोर्ट टी-1 (2.263 किमी) और 3. तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी)। यह 16.076 किलोमीटर लंबी परियोजना राष्ट्रीय राजधानी के भीतर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। दिल्ली मेट्रो के फेज-श (ए) की कुल लागत 12014.91 करोड़ रुपये है, जिसे भारत सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर सभी कर्तव्य भवनों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे इस क्षेत्र के कार्यालय जाने वालों और आगंतुकों को सीधे ऑफिस तक पहुंचने में आसानी होगी। इस कनेक्टिविटी से दैनिक आधार पर लगभग 60,000 कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और 2 लाख आगंतुकों को लाभ होगा। ये कॉरिडोर प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को और कम करेंगे, जिससे जीवन जीने की सुगमता में वृद्धि होगी।

विवरण:

आर.के. आश्रम मार्ग झ इंद्रप्रस्थ सेक्शन, बॉटनिकल गार्डन - आर.के. आश्रम मार्ग कॉरिडोर का विस्तार होगा। यह सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसका वर्तमान में पुनर्विकास किया जा रहा है। एयरोसिटी झ आईजीडी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद झ कालिंदी कुंज सेक्शन, एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर का विस्तार होंगे। यह विस्तार हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी को राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी हिस्सों जैसे तुगलकाबाद, साकेत, कालिंदी कुंज आदि क्षेत्रों के साथ मजबूत करेगा। इन विस्तारों में कुल 13 स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें से 10 स्टेशन भूमिगत और 03 स्टेशन एलिवेटेड होंगे।

पूरा होने के बाद, कॉरिडोर-1 यानी आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी) पश्चिमी, उत्तरी और पुरानी दिल्ली की सेंट्रल दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। वहीं अन्य दो कॉरिडोर— एयरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टी-1 (2.263 किमी) और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी)— दक्षिण दिल्ली को साकेत, छतरपुर आदि के माध्यम से घरेलू हवाई अड्डे टर्मिनल-1 से जोड़ेंगे, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के भीतर कनेक्टिविटी में जबरदस्त वृद्धि होगी।

पेंटागन रिपोर्ट : भारत में 2026 से पहले होगा एक और अटैक? पाकिस्तान के बाद अब चीन तैयार, यहां टिकी ड्रैगन की नजर

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) ने हाल ही में कांग्रेस को सौंपी गई रिपोर्ट "चीन से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास - 2025" जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि चीन किस तरह अपनी रणनीति, सेना और युद्ध की तैयारी को तेजी से आधुनिक बना रहा है, खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बड़े टकरावों के लिए। यह कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है, बल्कि चीन की लंबी योजना का पूरा खुलासा है।

PLA को राष्ट्रीय शक्ति के हथियार के रूप में ढालना

रिपोर्ट का मुख्य दावा साफ है- चीन PLA को सिर्फ ताइवान संकट के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग इलाकों में दबाव बनाने, डराने और जरूरत पड़ने पर युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है। इसका एक निशाना अमेरिका की तरफ भी है। सेना अब चीन की विदेश नीति का सीधा औजार बन चुकी है।

ढील्लइॅङ्क्लल फीस्रङ्क१३

भारत के लिए रिपोर्ट में क्या खतरा बताया?

भारत के लिए यह रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि इसमें चीन की वही रणनीतियां एक साथ दिखाई देती हैं, जिन्हें भारत पहले से महसूस कर रहा है-

- LAC पर सैन्य दबाव
- हिंद महासागर में बढ़ती मौजूदगी
- तेज न्यूक्लियर और मिसाइल एक्सपेंशन
- साइबर और इन्फॉर्मेशन वॉर की तैयारी
- पाकिस्तान को रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना

भारत के लिए संकेत

रिपोर्ट बताती है कि चीन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें अब पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा हैं। भारत के लिए इसका मतलब यह नहीं कि ताइवान दूर की बात है, बल्कि यह कि चीन जिन सैन्य क्षमताओं को बना रहा है, वही हिमालय और हिंद महासागर में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब ताइवान को सिर्फ डायवर्जन बनाकर इस्तेमाल कर भारत को टारगेट किया जा सकता है।

शी जिनपिंग का 2027 लक्ष्य और ताइवान फैक्टर

पेंटागन के अनुसार, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने PLA को 2027 तक बड़े सैन्य लक्ष्य हासिल करने का आदेश दिया है। अमेरिकी आकलन इसे सीधे ताइवान संकट से जोड़ता है। यह चीन की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिससे वह एशिया का शक्ति संतुलन बदलना चाहता है।

एक ही सैन्य टूलबॉक्स, कई मोर्चे

ISR (खुफिया-निगरानी), सटीक हमला, एयर डिफेंस, साइबर, अंतरिक्ष समर्थन और लॉजिस्टिक्स-ये सभी क्षमताएं अलग-अलग थिएटर में इस्तेमाल हो सकती हैं। यानी चीन एक ऐसा मल्टी-यूज टूलबॉक्स बना रहा है, जिसमें भारत कई "संवेदनशील कीलों" के पास बैठा है।

LAC पर शांतिः राहत या रणनीतिक जाल?

रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत-चीन ने LAC के कुछ तनावपूर्ण बिंदुओं से पीछे हटने का समझौता किया। इसके बाद बातचीत और सामान्य दिखाने की कोशिशें हुईं। जैसे सब कुछ अब ठीक हो रहा हो।

अरुणाचल कैसे है निशाने पर?

रिपोर्ट साफ करती है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को बिना युद्ध के दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है-

- जगहों के नाम बदलना
- स्टेपल वीजा जैसे संकेत या पर्यटकों के अरुणाचल से होने पर उन्हें रोका जाना
- इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करना

यह सब सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि धीमी जबरदस्ती की तैयारी है।

बिना गोली चलाए दबाव बनाने की रणनीति

PLA को अरुणाचल में युद्ध की जरूरत नहीं है। वह गश्त घुसपैठ, अचानक सैन्य अभ्यास, हवाई दावे, सूचना अभियान और बुनियादी ढांचे के जरिए भारत की शासन लागत बढ़ा सकता है।

अरुणाचल को "सीमांत" नहीं, "मूल राज्य" मानना जरूरी

भारत को अरुणाचल में

- निगरानी और ड्रोन-रोधी सुरक्षा
- सड़क, पुल और एयरफील्ड
- विकास + कूटनीति की मजबूत कहानी

पर तेजी से काम करना होगा।

पाकिस्तान से J-10C और नया खतरा

रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 तक चीन ने पाकिस्तान को 20 J-10C फाइटर जेट दिए। यह चीन का अब तक का इकलौता J-10C निर्यात है। ये 2020 से ऑर्डर की गई कुल 36 यूनिट्स का हिस्सा हैं।

मई 2025 भारत-पाक हवाई संघर्ष और चीनी भूमिका

रॉयटर्स के मुताबिक, पाकिस्तान को मई 2025 के हवाई संघर्ष में बढ़त मिली क्योंकि उसने चीनी सेंसर, डेटा लिंक और J-10C का इस्तेमाल किया। यह सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि वास्तविक सैन्य बढ़त थी।

पाकिस्तान बना चीन का टेस्ट लैब

भारत के लिए साफ संदेश है- पाकिस्तान चीन के हथियारों के लिए

- तकनीकी
- स्ट्रेटजिक
- नैरेटिव

टेस्ट का ग्राउंड बन रहा है।

साइबर और सूचना युद्ध अब मुख्य हथियार

पेंटागन कहता है कि चीन अमेरिकी नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा साइबर खतरा है। संकट के समय वह, बिजली, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स को निशाना बना सकता है।

न्यूक्लियर विस्तारः 600 से 1000+ वारहेड्स

रिपोर्ट के अनुसार,

- 2024 में चीन के पास 600 से कम न्यूक्लियर वारहेड थे
- 2030 तक यह संख्या 1000+ हो सकती है
- DF-31B ICBM का परीक्षण
- "Launch on Warning" रणनीति

यह भारत-पाक संकट के समय चीन के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है।

हिंद महासागरः जहाजों की नहीं, लॉजिस्टिक्स की लड़ाई

रिपोर्ट कहती है कि मुकाबला बड़े नौसैनिक युद्ध से ज्यादा

- पनडुब्बी एंटी युद्ध
- सी- सर्विलांस
- पाकिस्तान की उपस्थिति पर केंद्रित होगा।

चीन की कमजोरियां

रिपोर्ट यह भी मानती है कि PLA में भ्रष्टाचार, युद्ध का कम अनुभव, इंजन और तकनीकी बाधाएं, विदेशों में मिलिट्री बेस अभी पूरी तरह सक्षम नहीं होना उसके लिए बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। लेकिन चीन इन कमियों से तेजी से सीख रहा है। अगला एक दशक भारत के लिए तैयारियों का दशक होगा। यही तैयारियां आगे की सुरक्षा और युद्ध की तस्वीर को तय करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से गांधीनगर में टाइप-1 डायबिटीज कार्यक्रम का राज्यव्यापी प्रारंभ

- दूरदराजी क्षेत्रों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टाइप-1 डायबिटीज के उपचार का लाभ देकर इस रोग से पीड़ित सभी बच्चों को उपचार अंतर्गत लाने का स्वास्थ्य सेवा-उन्मुखी दृष्टिकोण
- मुख्यमंत्री ने टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित एक भी बच्चा उपचार सुविधा से वंचित न रह जाए; ऐसी सघन व्यवस्था की मंशा व्यक्त की
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए राज्य सरकार ने प्रिकॉशन, प्रिवेंशन तथा पॉजिटिव लाइफस्टाइल पर फोकस किया है : मुख्यमंत्री

गांधीनगर, 24 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में टाइप-1 डायबिटीज (जुवेनाइल डायबिटीज) से पीड़ित एक भी बच्चा उपचार-सुविधा से वंचित न रहे; ऐसी सघन उपचार व्यवस्था की राज्य सरकार की मंशा व्यक्त की है।

श्री पटेल ने टाइप-1 डायबिटीज (जुवेनाइल डायबिटीज) उपचार-नियंत्रण कार्यक्रम का बुधवार को गांधीनगर से प्रारंभ कराते हुए यह मंशा व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि राज्य के दूरदराजी क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में भी टाइप-1 डायबिटीज के उपचार का लाभ उपलब्ध हो और इस रोग से पीड़ित सभी बच्चों को उपचार अंतर्गत लाया जाए; ऐसे स्वास्थ्य सेवा-उन्मुखी दृष्टिकोण से हम यह राज्यव्यापी अभियान शुरू कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वस्थ एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प किया है। इसके लिए उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति को भी श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने हेतु आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा-देखभाल योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं; लोग निरोगी रहें, इसके लिए प्रधानमंत्री ने योग के प्रचार-प्रसार को भी महत्व दिया है। इसके बावजूद अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए, तो आयुष्मान कार्ड से सरकार उसके उपचार के लिए उसके साथ खड़ी है। योग से आयुष्मान की प्रधानमंत्री की यह विशिष्ट संकल्पना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने भी टाइप-1 डायबिटीज पीड़ित बच्चों के सटीक निदान एवं समय पर उपचार द्वारा इस रोग को नियंत्रित करने का संकल्प किया है।

उन्होंने राज्यव्यापी अभियान के प्रारंभ होने के अवसर पर टाइप-1 डायबिटीज पीड़ित बच्चों को उपचार किट का वितरण करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों के उपचार का बोझ परिवार पर न आ पड़े; इसके लिए राज्य सरकार निःशुल्क इंजेक्शन, ग्लूकोमीटर तथा अन्य आवश्यक उपचार सामग्री प्रदान करती है।

नव वर्ष पर देहरादून और मसूरी आने वालों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, इन बातों को फॉलो करें नहीं होगी परेशानी

(जीएनएस)।

NEW YEAR को लेकर देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। न्यू ईयर और वीकेंड पर देहरादून शहर से होते हुए मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट प्लान लागू कर दिया है।पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर तीन प्लान तैयार किए हैं।

जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही पार्किंग की जगह और केयरिंग कैपिसिटी की डिटेल भी जारी की है। देहरादून पुलिस ने मसूरी और देहरादून आने वाले पर्यटकों के लिए ट्रैफिक के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी खास निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही रेश ड्राइविंग और ट्रैफिक रुल्स को फॉलो न करने वालों को सख्त चेतावनी जारी की है।

दिल्ली से रुड़की / सहारनपुर से मोहण्ड होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान -

दिल्ली /रुड़की / सहारनपुर - मोहण्ड- आशारोड़ी - आई0एस0बी0टी0 - शिमला बाईपास - सैन्ट ज्यूड्स चौक - बल्लुपुर चौक - गढ़ी कैन्ट तिराहा - अनारवाला तिराहा - जोहड़ी गांव - मसूरी रोड़ - कुठाल गेट - मसूरी भेजा जायेगा ।

दिल्ली से हरिद्वार- ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान-

हरिद्वार / ऋषिकेश से हरावाला - मोहकमपुर फ्लाईओवर - जोगीवाला - व टर्न कैलाश अस्पताल - पुलिया नं0 06 - रिंग रोड़- लाडपुर तिराहा - सहस्त्रधारा क्रासिंग - आईटी पार्क - किरशाली चौक - साईं मन्दिर तिराहा - मसूरी डायवर्जन - कुठालगेट - मसूरी भेजा जायेगा ।

शहर में दबाव की स्थिति में प्लान इ

हरिद्वार - नेपाली फार्म तिराहा - भानियावाला तिराहा - एयरपोर्ट तिराहा - थानो रोड - महाराणाप्रताप चौक -लाडपुर तिराहा - सहस्त्रधारा क्रासिंग - आईटी पार्क - किरशाली चौक - साईं मन्दिर तिराहा - मसूरी डायवर्जन - कुठालगेट - मसूरी भेजा जायेगा

मसूरी से दिल्ली / सहारनपुर / रुड़की / ऋषिकेश / हरिद्वार / विकासनगर जाने हेतु वापसी रुट - मसूरी - कुठाल गेट - ओल्ड राजपुर रोड़ - राजपुर - साँई मन्दिर - किरशाली चौक - आई0टी0 पार्क - तपोवन बाईपास रोड - नालापानी चौक - तपोवन गेट - लाडपुर तिराहा - पुलिया नं0 06 - जोगीवाला से ऋषिकेश / हरिद्वार/ आई0एस0बी0टी0 की ओर जा सकेंगे ।

मसूरी में पार्किंग

पिक्चर पैलेस - वाहन क्षमता 70 कार

लण्ढौर रोड - वाहन क्षमता 60 कार

कैम्प्टी टैक्सी स्टैण्ड - वाहन क्षमता 250 कार एवं 20 बस

टाउन हॉल के नीचे - वाहन क्षमता 70 कार एवं 100 दुपहिया

किंग क्रेग - वाहन क्षमता 216 कार

मसूरी स्थित समस्त होटल - वाहन क्षमता 1800 कार

कम्पनी गार्डन रोड पर - वाहन क्षमता 30 कार

मैसानिक लॉज बस अड्डा / पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैण्ड - वाहन क्षमता 15 कार

विकास होटल पार्किंग कुलडी - वाहन क्षमता 20 कार

गज्जी बैंड में सड़क किनारे - वाहन क्षमता 500 कार

मसूरी में ट्रैफिक प्लान प्लान-अ

मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंग क्रेग से लाईब्रेरी व पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जायेगा

मसूरी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण उपलब्ध पार्किंग क्षमता का 70 प्रतिशत उपयोग होने पर प्लान इ को लागू किया जाएगा ।

प्लान-इ

इस प्लान के अन्तर्गत पर्यटकों के वाहनो को किंग क्रेग पार्किंग मे पार्क किया जायेगा जहां से पर्यटको को लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा । तथा आवश्यकतानुसार शटल सेवा के माध्यम से गंतव्य स्थल की ओर भेजा जायेगा ।

किंग क्रेग पार्किंग फुल होने की दशा मे प्लान उ को लागू किया जाएगा ।

प्लान-उ

इस प्लान के अन्तर्गत गज्जी बैण्ड से लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से पर्यटको को उनके गन्तव्य स्थल की ओर भेजा जाएगा

देहरादून शहर में ट्रैफिक प्लान - Pacific Mall / राजपुर रोड पर Traffic के दबाव होने पर मसूरी से घण्टाघर की ओर आने वाले Traffic को साईं मंदिर तिराहा से आईटी पार्क की ओर Divert किया जायेगा ।

Annexe / CSD तिराहा (नियर राजभवन) से दिलाराम चौक की ओर आने वाले Traffic को जोहड़ी गांव होते हुए Divert किया जायेगा ।

घण्टाघर पर Traffic दबाव होने की स्थिति में ओरियन्ट चौक / बुद्धा चौक / तहसील चौक से Traffic को आवश्यकतानुसार Divert किया जायेगा ।

देहरादून में पार्किंग व्यवस्था

रेंजर्स ग्राउण्ड, नियर बुद्धा चौक - पार्किंग क्षमता 300 कार

परेड ग्राउण्ड, नियर तिब्बती मार्केट - पार्किंग क्षमता 100 कार

पुराना रोडवेज बस अड्डा नियर तहसील चौक - पार्किंग क्षमता 80 कार

काबुल हाउस नियर सर्वे चौक - पार्किंग क्षमता 60 कार

कनक चौक मल्टीलेवल पार्किंग - पार्किंग क्षमता 70 कार

एमडीडीए पार्किंग नियर घण्टाघर - पार्किंग क्षमता 300 कार

राजीव गांधी कॉम्पलैक्स नियर तहसील चौक - पार्किंग क्षमता 400 कार

यहां रहेगी विशेष पुलिस टीमें तैनात

मसूरी डायवर्जन, सेंट ज्यूड्स चौक, ढाक पट्टी, ओल्ड राजपुर रोड, आशारोडी, कुठालगेट, दूधली, किरशाली चौक, अनुराग चौक, दिलाराम चौक, महिन्द्रा चौक, आराघर टी-जंक्शन, कौलागढ़ चौक, महाराणा प्रताप चौक, सर्किट हाउस तिराहा, सहस्त्रधारा क्रासिंग, झाझरा, जोगीवाला चौक, विधोली, बंगाली कोठी चौक, लालपुल, बालासुन्दरी मन्दिर तिराहा कैनाल रोड

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा के पंचकूला में 'सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका' पर सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया

इतिहास, धर्म, अध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हरियाणा आज कृषि और सहकारिता के सहयोग से किसानों की समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर 'सहकार से समृद्धि' का नया मंत्र दिया और रोजगार के साथ-साथ समृद्धि को भी सहकारिता से जोड़ा

कृषि, पशुपालन और सहकारिता इन तीनों को जोड़कर हो रहा है 'सहकार से समृद्धि' का सृजन

कम पानी, प्राकृतिक खेती और कम रिस्क, यही आधुनिक कृषि के तीन स्तंभ हैं

मोदी जी ने नेतृत्व में कृषि, सब्सिडी निर्भरता की जगह सस्टेनेबल और मुनाफा कमाने की दिशा में आगे बढ़ रही है

सहकारिता पर आधारित 'भारत टैक्सी' से होने वाला अधिकतम मुनाफा ड्राइवरों के पास जाएगा, उन्हें बीमा जैसी अनेक सुविधाएँ मिलेंगी

टरढ पर 24 फसलें खरीदने वाला पहला राज्य है हरियाणा, 48 घंटे के भीतर होता है खरीदी का भुगतान

11 वर्षों में मोदी जी ने कृषि बजट पांच गुना से अधिक और ग्रामीण विकास बजट दुगुना से अधिक बढ़ाया

गृह मंत्री जी ने मिल्क चिलिंग सेंटर, लअऋ्रऊ के आटा मिल, फ्थ्ढंट प्लेटिनम कार्ड, मॉडल पैक्स का पंजीकरण और सहकारिता वर्ष के पोर्टल का लोकार्पण भी किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज हरियाणा के पंचकूला में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) द्वारा 'सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका' विषय पर आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, केन्द्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इतिहास, धर्म, अध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हरियाणा आज धीरे-धीरे कृषि और सहकारिता के सहयोग से किसानों की समृद्धि के नए आयाम लिख रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर कृभको द्वारा आयोजित इस सेमिनार में मिल्क चिलिंग सेंटर, लअऋ्रऊ का आटा मिल, फ्थ्ढंट प्लेटिनम कार्ड, मॉडल पैक्स का पंजीकरण और सहकारिता वर्ष का पोर्टल, जो पूरे देश की सहकारिता से जुड़ी सूचनाएँ सहकारिता से जुड़े सभी किसानों तक पहुँचाएगा, का लोकार्पण किया गया।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जीवन-यापन खेती, किसानी तथा पशुपालन पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि यदि हम कृषि और पशुपालन को स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में देखें, तो ये क्षेत्र बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। श्री शाह ने कहा कि देश में सबसे अधिक रोजगार यदि किन्हीं दो क्षेत्रों में सृजित होता है, तो वह कृषि और पशुपालन से ही होता है।

व्यापार समझौतों के तहत पेशेवर सेवाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं भारतीय व्यावसायिक सेवाओं के लिए वैश्विक बाजारों के द्वार खोलेंगी: वाणिज्य सचिव

वाणिज्य विभाग ने ह्ववैश्विक क्षितिज का विस्तार: भारतीय पेशेवरों के लिए अवसरह्व विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया

पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) के उपयोग और उनके प्रभाव के आकलन के तरीकों पर चर्चा की गई

(जीएनएस)।

वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने व्यावसायिक सेवाओं पर चिंतन शिविर का उद्घाटन करते हुए भारतीय व्यावसायिक सेवाओं के लिए वैश्विक बाजारों को खोलने के लिए हितधारकों के बेहतर समन्वय, घरेलू परितंत्र में सुधार और विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत व्यावसायिक सेवाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के महत्व पर जोर दिया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) के सहयोग से 23 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में ह्ववैश्विक क्षितिज का विस्तार: भारतीय पेशेवरों के लिए अवसरह्व विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, वाणिज्य सचिव ने देश की आर्थिक वृद्धि के लिए सेवा व्यापार के महत्व पर जोर देते हुए माल निर्यात की तुलना में घरेलू मूल्यवर्धन में इसके मजबूत योगदान पर जोर दिया।

श्री अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि देश का जनसांख्यिकीय लाभांश व्यावसायिक सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने की अपार क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि इस क्षमता को साकार करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और पेशेवरों को बदलते वैश्विक बाजार की जरूरतों और तकनीकी विकास के अनुरूप उन्नत कौशल से लैस करना महत्वपूर्ण है। वाणिज्य सचिव ने कहा कि व्यावसायिक सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक खुलापन भारत की अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। उन्होंने पेशेवर संगठनों को ज्ञान साझा करने और बेहतर सहयोग के लिए मंच प्रदान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करने और उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री दर्पण जैन ने चिंतन शिविर का संदर्भ प्रस्तुत किया। आईसीएआई के अध्यक्ष सीए चरणजोत सिंह नंदा, भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) के अध्यक्ष श्री (डॉ.) टी. दिलीप कुमार और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) के अध्यक्ष प्रोफेसर अभय विनायक पुरोहित ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। आईसीएआई के उपाध्यक्ष सीए प्रसन्ना कुमार डी और एसईपीसी की अध्यक्ष डॉ. उपासना अरोरा ने भी उद्घाटन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित किया।

चिंतन शिविर को चार सत्रों में आयोजित किया गया। इनमें (क) वैश्विक स्तर पर काम करने योग्य पेशेवर बनाना; (ख) पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को मजबूत करना; (ग) नेटवर्क विकसित करना - विदेशों में पेशेवर अध्यायों का गठन और विस्तार; और (घ) व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना शामिल था।

चिंतन शिविर ने पेशेवर संगठनों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ भारत में समकक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया।

जनसुनवाईः में फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश

(जीएनएस)।

पीलीभीत। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को विस्तार से सुना। उन्होंने सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।जनसुनवाई के दौरान दर्जनों फरियादियों ने अपनी परेशानियां बताईं, जिनमें

पारिवारिक विवाद, जमीन हड़पने, धमकी आदि मामले शामिल थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने हर मामले को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। उनका कहना था कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान ही पुलिस की सच्ची सेवा है।इस आयोजन से फरियादियों में काफी उत्साह दिखा और उन्होंने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि ऐसी जनसुनवाई नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि कोई भी शिकायत लंबित न रहे।

लव जिहादी शिक्षक दिलनवाज गिरफ्तार, छात्रा से 5 साल तक शारीरिक शोषण

(जीएनएस)।

पीलीभीत,माधोटांडा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक शिक्षक ने अपनी छात्रा को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ 5 साल तक शारीरिक शोषण किया। आरोपी शिक्षक दिलनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपों की जानकारीः

- दिलनवाज ने अपनी छात्रा को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

- उसने छात्रा को धर्मांतरण के लिए दबाव डाला और उसे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया।

- जब छात्रा ने इसका विरोध किया, तो उसने उसे बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

- छात्रा को 4 दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया और उसे खाने के लिए सिर्फ नमकीन बिस्किट दिए गए।

पुलिस की कार्रवाईः

- पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक दिलनवाज को गिरफ्तार कर लिया है।

- पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

- पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी ने अन्य युवतियों को भी अपने चंगुल में तो नहीं फंसाया है।

आरोपी की जानकारीः

- आरोपी शिक्षक दिलनवाज की उम्र लगभग 35 साल है और अन्य विवरण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं।

- आरोपी शिक्षक की दो बेटियां हैं और वह 12 वर्ष पूर्व शादी कर चुका है।

पूरनपुर-आसाम हाईवे पर ओवरलोड वाहनों का तांडवः हर पल हादसे को दे रहे खुली दावत

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पूरनपुर-आसाम हाईवे पर ओवरलोड वाहनों का राज जारी है। भारी मात्रा में लदे ट्रक और डंपर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जिससे यात्रियों की जान पर बन आई है। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग मूकदर्शक बना हुआ है।स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ओवरलोड वाहन सड़कों को तोड़-फोड़ रहे हैं और ब्रेक फेल होने

या टायर फटने जैसे हादसों को न्योता दे रहे हैं। हाल ही में एक ट्रक के पलटने से दो लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई सुधार नहीं दिख रहा। अफ्छड कार्यालय पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं—क्या विभाग जानबूझकर अनजान बन रहा है?ग्रामीणों ने बताया, "रात के अंधेरे में ये वाहन चेकपोस्टों से बचकर निकल जाते हैं। चालान काटने के नाम पर आंखें मूंद ली जाती हैं।" परिवहन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जिला प्रशासन ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया है।हाईवे पर यातायात बढ़ने के साथ सुरक्षा चिंताएं और गंभीर हो गई हैं। ओवरलोडिंग पर सख्ती न हुई तो बड़े हादसे निश्चित हैं।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा से सहयोग से पीड़िता के राशन कार्ड में ऐड हुआ यूनिट

पूरनपुर पूर्ति निरीक्षक कार्यालय के कई बार चक्कर लगाने के बाद महिला ने प्रफुल्ल मिश्रा से शिकायत

पूरनपुर। (जीएनएस)। इन दिनों राशन कार्ड नए बनने और यूनिट ऐड करने की समस्या चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा समस्या को गंभीरता से संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है जिससे पीड़ित लोग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं उसके बाद भी उन्हें मिल रहा है तो सिर्फ समय ऐसा ही एक मामला पूरनपुर के क्षेत्र से सामने आया है यहां पर काफी लंबे समय से मुस्लिम पीड़िता के राशन कार्ड पर उसकी पुत्री का नाम नहीं दर्ज हुआ था इसके बाद विभाग में संपर्क करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि फरवरी के बाद ही आपका यूनिट राशन कार्ड में ऐड किया जा सकता है जिसके बाद पीड़िता ने अपने संपर्क के माध्यम से अपनी शिकायत को भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर विभागीय अधिकारियों को पीड़िता का यूनिट ऐड करने को कहा इसके बाद

तुरंत पीड़िता के राशन कार्ड में उसकी पुत्री का यूनिट ऐड किया गया और हर पात्र व्यक्ति को समय से समस्या का समाधान मिल सके क्योंकि भाजपा सबका साथ सबका विकास का दावा करती है लेकिन कुछ विभागीय लापरवाही के कारण जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है यदि भविष्य में ऐसा कोई भी मामला सामने आता और किसी विभागीय अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और हम उसके सेवक हैं। पीलीभीत भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा के इस सहयोग से पीड़िता और सभी संबंधित लोगों ने उनके कार्य की खूब सराहना की।

गांधी सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया

(जीएनएस)।

पीलीभीतः गांधी सभागार में हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है जिसका सामना

महिलाएं अक्सर करती हैं। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करना अनिवार्य है जो महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें।

कार्यशाला में उपस्थित लोगों को इस अधिनियम के प्रावधानों और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, कार्यस्थल पर एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने के महत्व पर भी जोर दिया गया।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे जिन्होंने कार्यशाला में सक्रिय भाग लिया और अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए। इस तरह की कार्यशालाएं निश्चित रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा माघ मेला-2026 की तैयारियों का निरीक्षण कर कार्य प्रगति का लिया गया जायजा

(जीएनएस)।

प्रयागराज 24 दिसम्बर

पुलिस आयुक्त श्री जोगेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा, मेलाधिकारी श्री ऋषिराज, नगर आयुक्त श्री सीलम सांई तेजा, अपर पुलिस आयुक्त डॉ अजय पाल शर्मा, एसपी मेला श्री नीरज पाण्डेय ने माघ मेला-2026 के दृष्टिगत हो रही तैयारियों का निरीक्षण कर कार्यप्रगति का जायजा लिया तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन व यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत आईसीसीसी में बनाये गये कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मेला क्षेत्र भ्रमण कर संत-महात्माओं को विद्युत, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति तथा अवसंरचनात्मक व्यवस्थाओं की प्रगति को देखा। उन्होंने सेक्टर-4 में महावीर पाण्डुन पुल के पास गंगाजी के द्वारा हो रहे कटान का निरीक्षण किया तथा जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई को कटान को रोके जाने हेतु अवरोधात्मक उपाय करने के निर्देश दिए है। वरिष्ठ अधिकारियों के

द्वारा खाकचौक में संत-महात्माओं के साथ बैठक कर प्रशासन के द्वारा उन्हें उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

तत्पश्चात पुलिस आयुक्त ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईसीसीसी में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा शहर व मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता, उनकी लोकेशन तथा उनकी विजुअल को चेक करते हुए लाइव फीड को देखा। उन्होंने कंट्रोल रूम में ऐसे लोगो को नियुक्त करने के निर्देश दिए है, जिन्हें कम्प्यूटर तथा सीसीटीवी की तकनीकी जानकारी के साथ मेला क्षेत्र व जनपद के अन्य क्षेत्रों की जानकारी हो। उन्हें सीसीटीवी कैमरा किस क्षेत्र का विज़ुअल दिखा रहा है, उसकी लोकेशन एवं क्षेत्र की अच्छी जानकारी हो। उन्होंने पुलिस विभाग के जनपद में पूर्व से तैनात अनुभवी लोगो को कंट्रोल रूम में नियुक्त करने के साथ ही अच्छे से सभी का अच्छे से प्रशिक्षण कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कंट्रोल रूम में बने रेडियो कक्ष में थाने, चौकियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की अद्यतन लिस्ट भी चस्पा कराये जाने के लिए कहा है, जिससे किसी इमरजेंसी के दौरान शीघ्रता से सम्पर्क किया जा सके तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सके।

इसके पूर्व सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मेला क्षेत्र में बनाये गये अस्थायी पुलिस कार्यालय में बैठक कर सुरक्षा, भीड़, यातायात प्रबंधन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बंध में बैठक की गयी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर श्री सत्यम मिश्र सहित अन्य सभी सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक हुई सम्पन्न।

(जीएनएस)।

पीलीभीतः- 24 दिसम्बर 2025/जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति कि वर्ष 2025 में 12वीं बैठक गांधी सभागार में आहूत हुई। उक्त बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोहरे में बढ़ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश भर में दिनांक 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाए जाने हेतु दिए गए निदेशों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंधित स्टेकहोल्डर विभागों को सड़क सुरक्षा माह का सफलतापूर्वक आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी मार्ग पर ढाबा इत्यादि के किनारे कतारबद्ध खड़े होने वाले वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें मुख्य मार्ग से हटवाया जाए ताकि कोहरे में पीछे से आ रहा कोई वाहन खड़े वाहनों से ना टकरा जाए। जनपद में पूरनपुर मार्ग एवं बीसलपुर मार्ग पर संचालित दोनों टोल प्लाजा के कार्यदायी संस्था के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को कोहरे में सुरक्षित परिवहन के लिए जागरूक किए जाने हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा अनाउंसमेंट करवाते रहें तथा टोल प्लाजा पर एंबुलेंस एवं क्रेन सर्विस हमेशा उपलब्ध रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके। टोल प्लाजा के वाहनों की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में ट्रामा सेंटरों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए तथा निजी अस्पतालों में चल रहे ट्रामा सेंटरों को सरकारी स्कीमों से लिंक किया जाए ताकि दुर्घटना पीड़ितों का वहां निशुल्क इलाज सुनिश्चित हो सके साथ ही समस्त ब्लैक स्पॉट्स पर एंबुलेंस सेवा हमेशा उपलब्ध रखी जाए।

जिलाधिकारी द्वारा शासन की ओर

से चलाई जा रही राहवीर योजना जिसमें घायलों को अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति को राहवीर मानते हुए उसे रू. 25000 तक के प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जाती है का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए। इस योजना के होर्डिंग्स समस्त थाना थाना परिसरों, ब्लॉक परिसरों एवं पंचायत भवनों में लगाए जाएं। कोहरे में वाहनों के सुरक्षित परिवहन हेतु सभी मार्गों पर सफेद पट्टी लगाने का कार्य तत्काल सुनिश्चित कर लिया जाए। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि एनएसएस, एनसीसी एवं सिविल डिफेंस के केडेट्स को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जन सामान्य को प्रेरित करने हेतु कार्य योजना बनाकर उसे लागू करवाया जाये। पूरनपुर टनकपुर नए बाईपास पर नीचे से गुजर रही विद्युत लाइन से दुर्घटना की संभावना को देखते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को इनकी ऊंचाई बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

एआरटीओ वीरेंद्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में हो रही दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि जनपद में सर्वाधिक दुर्घटनाएं गजरौला थाना क्षेत्र, जहानाबाद थाना क्षेत्र एवं बीसलपुर क्षेत्र में हो रही है। जनपद में डिवाइडरहीन समस्त मुख्य मार्गों पर मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराने एवं मोटरसाइकिल के अन्य वाहनों से टकराने से होने वाली की संख्या अधिक है। जनपद में होने वाली सड़क दुर्घटना में 70: से 80: तक प्रत्येक दुर्घटना में कोई ना कोई मोटरसाइकिल सम्मिलित रही है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में ऐसे क्षेत्र का पुलिस, परिवहन एवं कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण का दुर्घटना होने की बारंबारता का कारण जानकर उसमें हो सकने वाली अपेक्षित कार्यवाही का विवरण एकत्र का सुरक्षात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। असम चौराहे पर निर्माण अधीन फ्लावर तेजी लाई जाने हेतु कार्यदायी संस्था एनएचपीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया। बीसलपुर बिलसंडा मार्ग पर स्थित ब्लैक स्पॉट्स केचुआ पुल पर वन विभाग द्वारा रुकी गई कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पोर्टल पर आवश्यक सूचना अपलोड करते हुए कार्रवाई सुरक्षात्मक कार्यवाही तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए गए जिलाधिकारी द्वारा ओवर स्पीडिंग के कारण जनपद में बढ़ ही दुर्घटनाओं का निराकरण करने हेतु ऐसे मार्गों का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए गए जहां चालकों द्वारा ओवर स्पीडिंग ज्यादा की जा रही है ऐसे स्थान पर पुलिस बैरियर लगवा कर ओवर स्पीडिंग एवं हेलमेट के चालानों की संख्या बढ़ाई जाए। गन्ना वाहनों को निर्धारित हाइट तक ही गन्ना ले जाने हेतु चीनी मिलों के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया साथ ही उनसे कहा गया कि सभी ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टिव टेप एवं फ्लोरेंस पेंट अवश्य लगाया जाए ताकि रात्रि एवं कोहरे में ऐसे वाहन दूर से दिखाते रहें, गन्ना वाहनों को मुख्य मार्ग पर ना खड़ा किया जाए। उन्हें निर्धारित यार्ड एवं फैक्ट्री परिसर में ही खड़ा कराया जाए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आलोक शर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात विधि भूषण मौर्य, एआरटीओ वीरेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राजेश चौधरी, एनएचपीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता शशांक भार्गव, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव, एनएचएआई के अभियंता, मोर्थ के अभियंता नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी, चीनी मिलों के प्रबंधक एवं अन्य स्टेकहोल्डर विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्राकृतिक खेती से बढ़ रही किसानों की आय, सरकार व वैज्ञानिक संस्थानों का सहयोग

(जीएनएस)।

पीलीभीत :- 24 दिसम्बर 2025/रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में

सरकार और कृषि वैज्ञानिक संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला गंगा समिति पीलीभीत के द्वारा नमामि गंगे के तहत गोमती उद्गम स्थल पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ और उसके व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से जहां उत्पादन लागत में कमी आती है, वहीं किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारें प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर, किसान गोष्ठियां और प्रदर्शन प्लॉट के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रही हैं।

कृषि विभाग के अनुसार गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, घनजीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक संसाधनों से तैयार खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है और फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। जिले के प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का कहना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर होने वाला खर्च लगभग समाप्त हो गया है, जबकि बाजार में प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण उन्हें बेहतर मूल्य मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती से जुड़ी योजनाओं के तहत किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। कृषि विभाग का दावा है कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती का दायरा और बढ़ेगा, जिससे खेती टिकाऊ बनेगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।

उप प्रभागीय वन अधिकारी रमेश चौहान, द्वारा अवगत कराया गया है कि टेहरी के द्वारा शुरू की गयी कार्बन क्रेडिट योजना के तहत 7 यूकेलिप्टस के पौधे लगाने पर रुपये 500 के हिसाब से किसानों को दिया जायेगा इससे किसानो को खेती के साथ आर्थिक लाभ होगा।

कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉ एसवएसव ढाका, उप कृषि निदेशक राममिलन परिहार, सहायक विकास अधिकारी दिलीप कुमार, उप प्रभागीय वन अधिकारी रमेश चौहान, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की यूपी हेड सोनालिका सिंह, जिला परियोजना अधिकारी सौरभ प्रताप सिंह, कनिष्ठ अनुसंधान सहायक डॉ. आदर्श कुमार, गंगा समिति के सदस्य निर्भय सिंह व योगेश्वर सिंह सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।